

धृतराष्ट्री परिवारवाद और सुदामाई परिवारवाद में एक नैतिक जंग...

महाभारत काल में पुत्र सोहो में अंधे हुए राजा धृतराष्ट्र और मित्र प्रेम में लाचार हुए सुदामा कभी आपस में मिले थे, इसका कोई पौराणिक जिक्र भले न हो, लेकिन कलियुग में यह भेंट संभव हुई है। न केवल संभव हुई बल्कि इस डायलॉग के साथ हुई कि सुदामा तुम तय कर लो कि तुम्हें सुदामा ही रहना है या फिर धृतराष्ट्र बनना है। इस संवाद में चेतावनी भी है और धमकी भी। चेतावनी इस बात की कि गरीब सुदामा को कभी सप्तांश धृतराष्ट्र बनने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए और धमकी इस बात की कि अगर तुमने सुदामा की औकात से बाहर निकलने की कोशिश की तो राजनीतिक आख्यानों में भले तुम्हे अमरत्व हासिल हो जाए, लेकिन सियासी जिंदगी में तुम्हारी भूषणहत्या भी हो सकती है।

द्वापर युग का यह समूचा सदभू (पाराणक स्त्रीता के अनुसार) वर्तमान कलियुग के 5126 वें वर्ष में लोकतांत्रिक भारत में हो रहे 18 वीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाले छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने के उद्देश्य से दो नेताओं के बीच हुए संवाद का है। संवाद कहने के बजाए उसे एकालाप कहना ज्यादा उचित होगा। मीडिया में आई रिपोर्टों को सही मानें तो जो नैतिक डायलॉग बोला गया वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का था, जो दूसरी बार अपने पुत्र को छिंदवाड़ा से लोकसभा में भेजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ चार दशकों से कमलनाथ के सेवक रहे दीपक सक्सेना हैं, जो आर्थिक रूप से भले ही गब्बर बन गए हौं, लोकिन राजनीतिक रूप से सुदामा ही रहे। सुदामा होना केवल आर्थिक असमानता का प्रतिफल ही नहीं है बल्कि ऐसा भाग्यफल भी है, जिसमें लक्ष्मी और सत्ता सुंदरी दोनों गठबंधन कर याचक को ठेंगा दिखाती रहती हैं। दीपक सक्सेना नामक पात्र की सियासी ट्रेजेडी यही है कि तमाम वफादारियों के बाद भी उनके हिस्से में दरी उठाने का काम ही आया है। उनका कमलनाथ भक्त होना ही मानो इस राजनीतिक अभिशाप का कारण है। लिहाजा इस चुनाव में उन्होंने कमलनाथ से नाल तोड़कर कमलदल से जोड़ने की जुरत की तो बदले में उलाहना मिला कि धृतराष्ट्र बनने की कोशिश भी न करना।

इसका दूसरा अथ यह भा है कि एक हास्तनापुर में एक हा धृतराष्ट्र रह सकता है। या यूं कहें कि पुत्र मोह पालने का विशेषाधिकार भी उन्हीं को है, जो सत्ता सम्पन्न हैं। सत्ता में जमे हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जमे रहना चाहते हैं। यह जनता का पुनीत कर्तव्य है कि वह एक पीढ़ी के इन्वेस्टमेंट पर कई नस्तों को राजनीतिक लाभांश देती रहे। राजनेताओं के लिए अपने पुत्र/पुत्री/ पती आदि के सियासी कैरियर के आगे हर शै बेमानी है। कोई सुदामा अगर उसे चुनौती देने की धृष्टाता करेगा भी तो वह आंखों के साथ हाथ- पैरों से भी हाथ धो बैठेगा। यूं तो धृतराष्ट्र और सुदामा की कहानी में कहीं कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। ये सारा ताना बाना उस कूटनीतिज्ञ और भगवान कृष्ण के माध्यम से है, जो धृतराष्ट्र को पुत्र मोह से बचने की समझाइश देते हैं और नाकाम रहते हैं दूसरी तरफ सुदामा को दोस्ती का वास्ता देकर धौतिक आकाश्वाओं को तुम करने की कोशिश करते हैं। पुराणों में सुदामा के पिता का तो उल्लेख है कि वो राक्षसराज शंखचूड़ के पुत्र थे। शंखचूड़ को ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान था। लेकिन सुदामा के पुत्रों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चूंकि सुदामा राजनेता नहीं थे, इसलिए उनके पुत्रों के राजनीतिक और आर्थिक भविष्य की विनाशक तरफे की याज पाराकर्मणे को भी महसूस नहीं हुई देखें।

चत्ता करने का गरज पुराणकारों का भा महसूस नहा हुइ हागा। ब्राह्मण सुदामा मूलतः उस समाजवादी सोच की उपज थे, जिसमें अमेरी के बजाए गरीबी के समान वितरण पर ज्यादा जोर रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि दीपक सक्सेना के भाग्य में सुदामा होना ही बदा है। द्वापर युग में योगीराज कृष्ण ने अपने इस बाल मित्र को दोस्ती की खातिर जो कुछ माल-ताल दे दिया, उसे सुदामा को अपना सौभाग्य समझ कर संतुष्ट रहना चाहिए। इससे ज्यादा की उम्मीद पालना भी अपने आप में राजनीतिक अपराध है। आखिर नौकर, नौकर है और मालिक, मालिक 13 यह सही है कि दीपक सक्सेना कमलनाथ की कृपा से ही चार बार विधायक, एक बार मंत्री और एक बार प्रोटोटेम स्पीकर बने। लेकिन जब उनके राजनीतिक अरमान उरुज पर थे, तभी उनका पता काट दिया गया। स्वामी की खातिर पद और पावर गंवाने की ऐवज में उन्हें कुछ नहीं मिला। जब छिंदवाड़ा से लोकसभा के लिए किसी को भेजने की बात आई तो कमलनाथ ने अपने पुत्र नकुलनाथ को चुना। गौरतलब है कि राजनीति में सेवा के बदले मेवा मिलने का गणित इस बात पर निर्भर करता है कि आपका स्वामी कौन है, स्वर्य धृतराष्ट्र है अथवा कृष्ण। बहराल, कांग्रेस में अपनी उपेक्षा और स्वामीभक्ति के बदले मिली दुकार से दुखी दीपक सक्सेना ने भाजपा में जाने की हिमाकत की, जो उन कमलनाथ को रास नहीं आई, बावजूद इसके कि खुद उनके पुत्र समेत पाला बदलने की सुर्खियाँ मीडिया में चली थीं। तब भी लक्ष्य एक ही था पुत्र की कुर्सी बचाना। अब भी मक्सद वही है। फर्क इतना है कि पुत्र प्रेम का यही पासवर्ड दीपक सक्सेना ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लिंक ओपन करने के लिए डालना चाहा तो वो कमलनाथ का कोपभाजन बन गए। और तो और कमलनाथ की पुत्रवधु प्रिया नाथ ने भी दीपक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कमलनाथजी ने जिनकी मदद की, वही अग्नि परीक्षा के बक्त उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उधर लगातार मिल रहे दास ट्रीटमेंट से आहत दीपक ने पहले तो अपने बेटे अजय को भाजपा में भेजा और खुद भी भगवा धारण करने की तैयारी में थे। तभी उन्हें अल्टीमेटम दिया गया कि वो धृतराष्ट्र और सुदामा में से कोई एक ऑंशन को आट कर लें। यहां दीपक सक्सेना की 'गलती' यही है कि उन्होंने धृतराष्ट्री परिवारवाद के बदले सुदामाई परिवारवाद को खड़ा करने की कोशिश की। चरण बंदन के बदले माथे पर तिलक चंदन मांगा। परिवारवादी राजनीतिक संस्कृति में यही महापाप है। वरना धृतराष्ट्र खुद अपनी निश्चाण आंखों के साथ पाला बदल लें तो यह राजनीतिक पैंतरा होता है और सेवक अपनी जीवित आंखों के साथ दूसरे का दामन थाम ले तो तो स्वामीद्वारा कहलाता है। है न गजब थ्योरी! वैसे भी धृतराष्ट्रवादी चिंतन में सत्ता की रेवड़ियाँ अपनों के अकाउंट में ही ट्रासंफर होती हैं। लोकतंत्र में इसके औचित्य को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस ढांग से ताकिंक जामा पहनाया, वह अनूठा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा वाले (हालांकि परिवारवाद वहां भी है) हम पर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं, इसीलिए मैंने इस बार अपने परिवार के लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए हैं। इस धृतराष्ट्रवादी चुनावी एपीसोड में कमलनाथ ने इमोशनल कार्ड का ब्रह्मास्त्र चल दिया है। जिसका एक निशाना खुद दीपक सक्सेना भी हैं। जानकारों का कहना है कि वहां भाजपा की गंगा में कितने ही आयातित नेताओं का शुद्धिकरण हो जाए, लेकिन कमलनाथ का भावनात्मक दांव बीजेपी की तमाम कोशिशों पर भारी पड़ सकता है। भाजपा अपने मिशन- 29 के तहत छिंदवाड़ा में कमलनाथ की नाल हर कीमत पर काटना चाहती है, लेकिन साम-दाम-दंड-भेद के बाद भी छिंदवाड़ा में इस बार चुनाव में 'कमल' नहीं खिल पाया तो मुश्किल कमलनाथ के बजाए कमलदल के कर्णधारों की बढ़ेगी।

कचातिवुः इस विवाद का कोई अंत नहीं..., क्षेत्रीय खींचतान के बीच सबसे पहले राष्ट्रीय हित पर विचार जरूरी

भारत और श्रीलंका के बीच स्थित कचातिवु द्वीप पर मौजूदा चुनाव के दौरान छिड़ी बहस के मुख्य निशाने पर मछुआरे हैं, जो महत्वपूर्ण वोटबैंक हैं। हरानी की बात नहीं कि राजनीति ने दोनों पड़ोसी देशों के नाजुक रिश्ते और कूटनीति को इस बहस में खाँच लिया है। यह भाजपा बनाम कांग्रेस की लडाई है



इसालए हमारा पास बहस का तासरा पक्ष है। मौजूदा बहस तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई के एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) जवाब को लेकर है। उन्होंने कहा है कि भारत का महत्वपूर्ण टुकड़ा देने से तमिलनाडु के मछुआरे भाइयों और बहनों के लिए परेशानी पैदा हो गई है। एक बीड़ियों में, उन्होंने श्रीलंका को कचातिवृ सौंपने में मिलीभगत के लिए कांग्रेस और द्रुमुक पर निशाना साधा। मीडिया के एक वर्ग द्वारा सामने लाए गए नए तथ्यों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मोदी ने उन्हें आंखें खोलने वाला और चौंकाने वाला बताया और इंदिरा गांधी सरकार पर राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उनकी पार्टी और गठबंधन के अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए।
प्रधानमंत्री मोदी की बयानबाजी का जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकर्जन खरगे ने पूछा कि क्या

मोदी सरकार एक पुराने समझौते और एक ऐसे मुद्दे को फिर से खोलना चाहती है, जो श्रीलंका के साथ संबंधों को खराब कर सकता

है। यह बयानबाज़ा भा है, लोकन एक चेतावनी भी, क्योंकि कोलंबो में मछुआरे और सरकार, दोनों इस मुद्दे पर काफी संवेदनशील हैं। चुनाव चाहे तमिलनाडु, भारत या श्रीलंका में हो और सत्ता में चाहे जो भी रहे, चुनाव से पहले या बाद में असली मुद्दा दोनों तरफ मछुआरों के मछली पकड़ने का अधिकार है। भारतीय क्षेत्र में मछली उत्पादन तेजी से कम हो रहा है और कई ट्रॉलर चलाने वाले भारतीय मछुआरों पर श्रीलंका तट के करीब पानी में मछली पकड़ने के आरोप लगाए गए हैं। स्वाभाविक रूप से इससे श्रीलंका परेशान है। यह कभी नहीं खत्म होने वाला मुद्दा है। इस क्षेत्र में सदियों से मछली पकड़ने वाले तमिलनाडु के मछुआरे कई बार कच्छात्रु से आगे श्रीलंकाई पानी में चले जाते हैं और उत्तरी श्रीलंकाई तट के पास मछली पकड़ते हैं। उन्हें श्रीलंकाई नौसेना गिरफ्तार कर लेती है। तमिलनाडु में राजनीतिक दल जब हंगामा करते हैं, तो केंद्र सरकार कूटनीतिक हस्तक्षेप करती है और फिर उन्हें छोड़ा जाता है। साल-दर-साल यह चक्र दोहराया जाता है और

इसका काइ अत नहा दखत। तमिलनाडु के राजनेता नियमित रूप से मांग करते हैं कि कच्चातिवु को श्रीलंका से बापस लिया जाए, क्योंकि भारत ने इसे बिना सोचे-समझे साँप दिया था। वर्ष 2008 में अन्नाद्रमुक और वर्ष 2013 में द्रमुक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन केवल यह बताया गया कि द्वीप की वर्तमान स्थिति एक समझौता है, जिसे पलटा नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि तमिलनाडु की सरकारें केंद्र सरकार से शिकायतें करती रही हैं। यह मुद्दा मूलतः मछुआरों का है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका ने 6,184 मछुआरों और 1,175 नावों को हिंसा सत्त में लिया है। यह सच है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और न ही इसके खत्म होने की संभावना है। इसमें किसी देश की संप्रभुता नहीं, बल्कि मछली पकड़ने का अधिकार शामिल है। यह ध्यान देना जरूरी है कि गुजरात के मछुआरों का पाकिस्तान के साथ विवाद है और पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के मछुआरा का बांगलादेश के साथ गुजरात में सौराष्ट्र एवं कछु सेकड़ों लोगों को पाकिस्तान बेंजल क्षेत्र में जाने के लिए हिंसा के लिया गया है और हजारों में तब तक के लिए बंद हैं, जब तक कि उनके मामले कूटनीतिक रूप से और दोनों देशों की अदालतों द्वारा हल नहीं हो जाते। तमिलनाडु में यह मुद्दा क्यों चर्चा में है? सिवाय इसके कि अभी लोकसभा के चुनाव हैं? यह मुद्दा मछुआरों के अधिकारों और वोट व सत्ता के लिए होड़ करने वाली दो द्विविध पार्टियों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित है। वर्ष 2009 में जातीय हिंसा खत्म होने के बाद से श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते धीरे-धीरे सुधरे हैं, क्या कच्चातिवु का मुद्दा इस रिश्ते को बिगाड़ने वाला है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चीन पूरे दक्षिण एशिया में भारत को धेरे का प्रयास कर रहा है। इस पूरे क्षेत्र में खींचतान को देखते हुए हमें सोचना होगा कि क्या इस तरह के धरेलू और चुनावी मुद्दे हमारे राष्ट्रीय हित में हैं!

शिक्षा जगतः कौचिंग राष्ट्र बनने को दिशा में देश, नौकरियों को पुनर्जीवित करने को सर्वोत्तम प्राथमिकता देना जरूरी

ग्रामीण भारत के 14 से 18 वर्ष की आयु वें युवाओं के बीच शिक्षा के निराशाजनक परिदृश्य पर रोशनी डालती है। बढ़ने वे कौशल में आठवीं कक्षा के 30 फीसदी ग्रामीण छात्र दूसरी कक्षा के मानक पाठ नहीं पढ़ सकते। इसी तरह अंकगणित कौशल में आठवीं कक्षा के 55 फीसदी ग्रामीण छात्र बुनियादी भाग करने में असमर्थ थे। जबविं अंग्रेजी समझ एवं कौशल में, आठवीं कक्षा के आधे ग्रामीण छात्र आसान वाक्यों का पढ़ने में असमर्थ थे और जो पढ़ सकते थे उनमें से लगभग एक तिहाई छात्र अर्थ बताने में असमर्थ थे। स्कूली शिक्षा में सीखने वे अपर्याप्त परिणामों को देखते हुए समकालीन भारत में कोचिंग संस्थानों का विस्तार होना स्वाभाविक है। शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट 2022 ने बताया कि कक्षा एक राष्ट्रीय आठवीं तक के 30.5 फीसदी ग्रामीण छात्रों का सशुल्क निजी कोचिंग कक्षाएं ले रहे थे स्कूली शिक्षा में मूलभूत कौशल और गहरा सोच कौशल की कमी के कारण निजी कोचिंग पर निर्भरता ज़रूरी हो गई है। जैसे जैसे छात्र उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कोचिंग पर निर्भरता बढ़ती जाती है। भारत एक कोचिंग राष्ट्र में बदल गया है, न केवल महानगरीय शहरों में, बल्कि छोटे शहरों में भी। सरकार नौकरियों की इच्छा, जो सामाजिक सुरक्षा वे साथ आती है, शायद ग्रामीण छात्रों को आगे बढ़ने के लिए यही एकमात्र रास्ता हो। भारत के 91 फीसदी कार्यबल अनौपचारिक रोजगार में है, जिसे सामाजिक बीमा के बिना रोजगार के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात् वृद्धावस्था पेंशन, मृत्यु/विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ इत्यादि रूप से वर्चित रोजगार। वर्ष 2022-23 में स्थातकों के लिए बेरोजगारी दर 13.4 फीसदी और स्नातकों दर और उससे ऊपर के लोगों वे लिए 12.1 फीसदी रही, जो राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी दर 3.2 फीसदी (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) से लगभग चार गुना है।



अंग्रेजी कौशल मुख्य घट जबकि आवादी की मुख्य शिक्षा का माध्यम हिंदी व परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए की आवश्यकता होती कोचिंग अपरिहार्य हो जाकी उम्मीदें ऊँची बनी हुईं को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं कोचिंग लेने के लिए प्रेस सफलता और विफलता व में कोचिंग एक महत्वपूर्ण सकती है। सभ्य गैर-अनुपलब्धता, रुकी हुई और सीमित सरकारी नौकरी

अभूतपूर्व प्रतिस्पद्य है, जिसने छात्रों द्यूशन और कोचिंग में धकेल दिया है। इसलिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार में तब्दील हुआ है, इसलिए निजी द्यूशन कोचिंग संस्थान तेजी से बढ़ रहे हैं। कोचिंग संस्थान लंबे समय तक अनियमित बाजार बने रहे, और शिक्यातयों और छात्रों की आत्महत्याओं बाद ही सरकार कोचिंग सेंटरों को संचालित करने के लिए दिशा-निर्देश लेकर आई। ‘कोचिंग सेंटर का पंजीकरण विनियमन, 2024’ दिशा-निर्देश को सेंटरों को भास्कर बढ़ा करने या सफलता-

हालांकि, इसका उपाय स्कूली शिक्षा, उच्च अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की नींव में सीखने के परिणामों में सुधार करना है इसके अलावा, हर कोई कोचिंग का खच नहीं उठा सकता और सरकारी नौकरी के आकांक्षा नहीं कर सकता। गैर-आद्योगिकीकरण और संरचनात्मक परिवर्तन के उलट होने की स्थिति में जो कुछ बचा है वह है गिर इन्हाँमी, जो बिना किसी सामाजिक सुरक्षा जाल के कार्यबल के केवल निर्वाह प्रदान करती है। इस प्रकार समकालीन भारत में नौकरियों को पुनर्जीवित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

